नकल पर नकेल, 146 पेपरों में जीरो पेपरलीक : बेढ़म

गृह और कारागार विभाग की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित

जयपुर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाते हुए अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध के खिलाफ राजस्थान पुलिस जीरो टोलरेंस की नीति अपनाकर सख्त कार्रवाई कर रही है। जनता के सम्मान, जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करना हमारी सरकार का प्रथम कर्तव्य है।

बेढ़म सोमवार को विधान सभा में गृह विभाग की (मांग संख्या-18) एवं कारागार विभाग की (मांग संख्या-19) अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्येय 'कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित' प्रजा के सुख में शासक का सुख निहित है, प्रजा के हित में उसे अपना हित दिखना चाहिए' के अनुरूप है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्ण संवेदनशीलता के साथ इस दिशा में अहम निर्णय ले रहे हैं। चर्चा के बाद सदन ने गृह विभाग की 116 अरब 57 करोड़ 7 लाख 84 हजार रूपए एवं कारागार विभाग की 3 अरब 68 करोड़ 47 लाख 11 हजार रूपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।

बेढ़म ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद अपराधियों में भय बढ़ा है। समठा अपराध की स्थिति में राज्य में वर्ष 2023 में जहां 2 लाख 31 हजार 240 प्रकरण दर्ज हुए थे। इसके बाद वर्ष 2024 में 2 लाख 13 हजार 351 प्रकरण ही दर्ज हुए। ऐसे में 17 हजार 889 प्रकरणों की कमी आई है। यह 7.74 प्रतिशत की गिरावट है। ये आंकड़े हमारी सरकार में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की स्थिति को दर्शाते हैं।

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का आदर्श वाक्य 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' है। यह नारी शक्ति के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को दर्शाता है। महिला संबंधित घटनाओं की रोकथाम और भयमुक्त वातावरण के लिए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के संचालन और 1 हजार कॉन्स्टेबल के पदों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। साथ ही, 65 एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया गया है। मोबाइल एप 'महिला हेल्पलाइन नंबर 1090' जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से ही महिला अपराधों में कमी आई है।

बेढ़म ने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में 19 परीक्षा पेपरों में से 17 के पेपरलीक हुए थे। उन पर एसआईटी का गठन कर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने युवाओं से जीरो पेपरलीक का वादा किया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की 1 जनवरी 2024 से आज तक 146 परीक्षाएं बिना पेपरलीक कराई गई। अब एसआईटी द्वारा गत सरकार के दौरान हुई 43 परीक्षाओं की जांच की जा रही हैं, जिनमें 16 में पेपरलीक की घटनाएं सामने आई है और 27 में अन्य अनियमितताएं पाई गई हैं। एसआईटी द्वारा अभी तक 331 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच जारी है। साथ ही, उपनिरीक्षक एवं प्लाटून परीक्षा-2021 में 91 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। इनमें कार्रवाई करते हुए 36 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को बर्खास्त किया है।

गृह राज्य मंत्री ने बताया कि साइबर क्राइम पर ऑपरेशन एंटी वायरस तथा साइबर शील्ड के तहत प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। सरकार ने साइबर क्राइम के जरिए आमजन की गाढ़ी कमाई के पैसे पर डाका डालने वालों पर अभियान चलाकर सख्ती कार्रवाई की है। इसमें 255 मामलों में प्रकरण दर्ज कर 543 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा गया है। वर्ष 2023 से 31 जनवरी 2025 तक साइबर अपराध की रोकथाम के लिए कुल 1 लाख 76 514 फर्जी मोबाइल नंबर एवं 1 लाख 35 हजार 372 मोबाइल आईएमईआई हैंडसेट ब्लॉक कराए गए।

जब आसन पैरो पर हो तब सदस्य मूवमेंट नहीं करेंगे : देवनानी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि जब आसन पैरों पर हो तब कोई भी सदस्य न तो बाहर से अन्दर आयेंगे और न ही अंदर से बाहर जायेंगे। जब आसन पैरों पर हो, तब सदन में सभी अपने सीटों पर बैठेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे। विधायक, आसन के बोलते वक्त अपनी सीटों से नहीं उठे और ना ही कोई बाहर से सदन में प्रवेश करें।

सोमवार को विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने सदन में व्यवस्था देते हुये विधायक से कहा कि सदन में प्रत्येक विधायक की बात को सुना जायें। जब विधायक सदन में अपनी बात रख रहे हो तब उन्हें टोका भी नहीं जायें। देवनानी ने कहा कि सभी विधायक भाषा में शालीनता का पूरा ध्यान रखें। किसी विधायक द्वारा सदन को संबोधित करते समय अन्य विधायक उनके सामने से ना निकलें। देवनानी ने कहा कि सदन की यह बहुत पुरानी परंपरा है। सदन में फोन पर बात करना प्रतिबंधित है। नाम पुकारने पर ही संबंधित सदस्य बोले। देवनानी ने कहा कि अनुदान मांगो पर संबंधित मंत्री और संबंधित अधिकारी का सदन में मौजूद रहना आवश्यक है।

भजनलाल सरकार के नेतृत्व में रीट और आरएएस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न : डॉ.सतीश पूनिया

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने रीट पात्रता परीक्षा 2025 के सफल आयोजन को लेकर

> ■ 'राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर गहलोत को दिया पाप का दंड'

भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ.सतीश पूनिया प्रेस से रूबरू हुए।

भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉ पूनिया ने कहा कि रीट परीक्षा निर्विघ्न रूप से आयोजित करवाने पर प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। भाजपा सरकार ने प्रदेशभर में शांतिपूर्ण रूप से रीट परीक्षा करवाई। जबकि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में रीट का पेपर आउट हुआ था और प्रदेश के 70 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था। गहलोत के कार्यकाल में रीट ही नहीं, पटवारी भर्ती, कांस्टेबल भर्ती, जेईएन भर्ती, एसआई भर्ती, लाईब्रेरियन भर्ती, वनरक्षक सहित 19 परीक्षाओं के पेपरलीक हुए। इसका नतीजा यह हुआ कि गहलोत के पाप का दंड राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके दिया।

पूनिया ने कहा कि कांग्रेस राज में प्रदेश में अराजकता का माहौल हो गया था। पेपरलीक की गूंज देशभर में पहुंची और राजस्थान पेपरलीक के मामले में देशभर में बदनाम हुआ। इसके लिए गहलोत और कांग्रेस सरकार सीधे तौर पर दोषी थी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ना केवल रीट परीक्षा का सफल आयोजन करवाया, बल्कि आरएएस भर्ती परीक्षा भी शांतिपूर्ण संपन्न करवाई। इतना ही नहीं, कांग्रेस राज में भर्ती परीक्षाओं के दौरान प्रदेश में घंटों नेटबंदी की जाती रही, जिससे आमजन परेशान हुआ और करोड़ों रूपए का व्यापार भी प्रभावित हुआ, लेकिन भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के दौरान नेटबंदी पर रोक लगाई। कश्मीर में आतंकवाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए नेटबंदी करने पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा मुद्दा बनाया जाता था, लेकिन बाद में इन्हीं कांग्रेसियों ने परीक्षाओं में नेटबंदी करना शुरू कर दिया था। भाजपा सरकार ने रीट और आरएएस भर्ती परीक्षा बिना नेटबंदी के शांतिपूर्ण संपन्न करवाई। ऐसे में भाजपा सरकार का अभिनंदन।

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेसी नेता अधिकांश तौर पर अपनी हार के लिए जिम्मेदार ईवीएम को बताते है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार का सत्ता से बाहर जाने के 10 कारणों में से मुख्य कारण पेपरलीक रहा है। पेपरलीक को लेकर सदन में और सदन के बाहर भी व्यापक आंदोलन हुए, कांग्रेस सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता था, कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस का दमनचक्र भी चलाया, लाठी के दम पर आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया।

छात्राओं ने विधानसभा को देखा

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से सोमवार को यहां राजस्थान विधान सभा में कानोडिया पी.जी महिला महाविद्यालय की राजनीति विज्ञान विषय की स्नातकोत्तर की छात्राओं ने मुलाकात की। महाविद्यालय की छात्राओं ने सोमवार को राजस्थान विधान सभा के सदन में प्रश्नकाल की प्रक्रिया को देखा और सदन में विधायकों की चर्चा को सुना। महाविद्यालय की प्राध्यापक डॉ. निमिषा गौड, संजू शर्मा और स्वाती ने छात्राओं के दल के साथ विधान सभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय को भी देखा।

अजय सिंह किलक ने नागौर एसपी पर आरोप लगाये

जयपुर। डेगाना विधायक और पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक ने गृह विभाग की अनुदान मांगों पर नागौर एसपी और इलाके की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। किलक ने कहा कि मैं सदन में आरोप लगा रहा हूं कि नागौर एसपी मेरे से व्यक्तिगत दुर्भावना रखते हैं, मेरे कई कार्यकर्ताओं से भी दुर्भावना रखते हैं। थांवला क्षेत्र के लोगों ने मुझे बताया कि वहां पर थानेदार पैसा लेकर अवैध बजरी निकलवाता है। हर ट्रक से पांच हजार और ट्रैक्टर-ट्रॉली से भी मोटी रकम वसूलता है। इस संबंध में मैंने व्यक्तिगत रूप से नागौर एसपी को जानकारी दी कि वहां थानेदार पैसे लेकर अवैध बजरी खनन करवाता है। मैंने एसपी से बात की तो उनका जवाब था मैं खुद रिश्वत नहीं लेता, तो मैंने कहा मैं भी रिश्वत नहीं लेता हूं मैं भी वहां का विधायक हूं। किलक ने कहा कि थांवला के थानेदार की मुख्यमंत्री से शिकायत की, तब जाकर उसे हटाया।

> ■ कहा, "नागौर एसपी मेरे से व्यक्तिगत दुर्भावना रखते हैं, मेरे कई कार्यकर्ताओं से भी दुर्भावना रखते हैं।"

जबकि नागौर एसपी ने उस थानेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सहायक वनपाल ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो उस थानेदार ने उससे ही बदतमीजी की।

शान्ति धारीवाल ने बहस के दौरान मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों पर तंज कसा। धारीवाल ने कहा कि टेलीग्राफ एक्ट की क्या हालत की है आपने। एक मंत्री कह रहा है मेरा फोन टेप हो रहा है, दूसरा मंत्री कह रहा है नहीं हो रहा। दूसरी बार मंत्री ने फिर कहा कि अब भी हो रहा है, क्या तमाशा है?

खाद्य सुरक्षा सूची से हटाई 23 हजार से अधिक यूनिट्स

जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 'गिव अप' अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने इस अभियान को आगामी 31 मार्च तक संचालित करने का फैसला किया गया है। जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार जयपुर में गिव अप अभियान का सफल संचालन किया जा रहा है। अभियान के तहत 2 मार्च तक 5 हजार 952 परिवार राशन कार्डों की 23 हजार 96 यूनिट्स को खाद्य सुरक्षा सूची से पृथक कर दिया गया है। वहीं, जयपुर में योजना के 244 अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी। शास्ति की गणना 27 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम अंकित होने की तिथि से नाम हटाने की तिथि तक उप व्यक्ति द्वारा जितना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है, अनुसार की जाकर मय ब्याज वसूली की जाएगी। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार ऐसे कार्मिकों की सूचियां तैयार की जा रही हैं एवं ऐसे कार्मिकों के संबंधित विभागों को वसूली की राशि कार्मिक के मासिक वेतन से कटौती करने हेतु लिखा जावेगा।